सत्यमेव जयते

आर्थिक समीक्षा 2017-18

खण्ड 1

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
आर्थिक प्रभाग
जनवरी, 2018

विषय सूची

अध्याय सं.	पृष्ठ सं	अध्याय का नाम
	v	**आभारोक्ति**
	vii	**प्राक्कथन**
	ix	**संकेताक्षर**
	xiii	**भारतीय अर्थव्यवस्था पर दस नए तथ्य**
		अर्थव्यवस्था की स्थिति: विश्लेषणात्मक सिंहावलोकन और नीतिगत संभावनाएं
1		**सिंहावलोकन: अल्पावधिक संदर्भ में सिंहावलोकन: मध्यावधि**
2		**माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक नूतन प्र. बंधक एवं संक्षिप्त विवेचना**
	32	भूमिका
	33	करदाता
	34	कर आधार तथा इसका स्थानिक वितरण
	35	फर्मों के पारस्परिक लेने-देने का आकार
	37	अन्तरर्राष्ट्रीय व्यापार, अन्तर-राज्यीय व्यापार और आर्थिक समृद्धि
	39	व्यापार में सर्वश्रेष्ठ: भारतीय निर्यात समानतावादी अपवादात्मकता
	40	भारतीय अर्थव्यवस्था में अनौपचारिकता
	42	निष्कर्ष
3		**निवेश और बचत में गिरावट और स्थिति में सुधार: भारत के संबंध में विभिन्न देशों का अनुभव**
	43	प्रस्तावना
	45	निवेश और बचत में शिथिलता की पहचान
	48	बचत बनाम निवेश: संवृद्धि पर प्रभाव
	51	निवेश में 'भारत जैसी' गिरावट से उबर पाना
	53	निष्कर्ष: भारत के लिए सबक
4		**राजकोषीय संघवाद और जवाबदेही में समन्वय: क्या इसमें निम्न संतुलन अवरोध हैं?**
	55	प्रस्तावना
	59	स्थानीय प्रशासन: क्या है
	63	राज्य और स्थानीय सरकारें: बिल्कुल भिन्न प्रश्न है
	65	निष्कर्ष: निम्न संतुलन पाश?
5		**क्या विकास में विलंबित अभिसृति एक बाधा बन जाती है? क्या भारत उससे बच सकता है।**

	68	प्रस्तावना
	71	किंतु.....
	72	चार प्रतिकूल परिस्थितियां (''होर्समैन'')
	81	भारत के लिए सबक
6		**जलवायु, परिवर्तन और कृषि**
	82	प्रस्तावना
	86	तापमान और वर्षा के सामयिक और स्थानिक पैटर्न
	88	कृषि उत्पादकता पर मौसम का प्रभाव
	93	किसानों की आमदनी पर प्रभाव
	95	निष्कर्ष और नीतिगत प्रभाव
7		**कन्या नहीं, पुत्र चाहिए: क्या विकास ही इस समस्या का समाधान है?**
	102	प्रस्तावना
	105	भारत और अन्य देश
	110	भारतीय राज्यों का निष्पादन
	111	पुत्र ही चाहिए: जन्म पर विषम लिंगानुपात
	112	पुत्र ''मेरा'' चाह: अंतिम संतान और ''अवांछित'' लड़कियों का लिंगानुपात
	116	निष्कर्ष
8		**भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का रूपांतरण**
	119	विज्ञान क्यों
	120	आगत और परिणाम: कुछ साक्ष्य
	124	परिणाम
	126	भारत में अनुसंधान और विकास विस्तार: भावी योजना
9		**व्यवसाय करने को आसान बनाने का अगला मोर्चा: समय से न्याय**
	131	परिचय
	1	विलम्बता और देरी: तथ्य
	1	विलम्बता और देरी: संभावित कारणों
	1	केन्द्रीय सरकार कर: प्रकरण अध्ययन
	1	न्याय के प्रशासन पर व्यय
	1	नीति निहितार्थ
		अनुबंध

आभारोक्ति

यह आर्थिक समीक्षा मिल–जुलकर किए गए कार्य और परस्पर सहयोग का परिणाम है। आर्थिक प्रभाग और मुख्य आर्थिक सलाहकार के कार्यालय से जिन व्यक्तियों का योगदान इस समीक्षा की रचना और प्रकाशन में मिला है, इनमें शामिल हैं: अर्चना एस॰ माथुर, संजीव सान्याल, एच॰ए॰सी॰ प्रसाद, ए॰एस॰सचदेवा, राजश्री रे, अरूण कुमार, एंटनी सिरियक, पी॰के॰ अब्दुल करीम, अश्विनी लाल, आशुतोष राराविकर, निखिला मेनन, अभिषेक आचार्य, रजनी रंजन, धर्मेन्द्र कुमार, आकांक्षा अरोड़ा, रबि रंजन, दीपक कुमार दास, एम॰ राहुल, अभिषेक आनंद, कनिका वाधवान, सोनल रमेश, खाई लेसिंहम, गौरव कटियार, नीरज श्रीवास्तव, विजय कुमार मान, रियाज अहमद खान, सलाम श्याम सुन्दर सिंह, मो॰ आफताव आलम, प्रद्युत कुमार पाइन, नरेन्द्र जेना, प्रवीन जैन, सुभाष चन्द, राजेश शर्मा, अमित कुमार केसरवानी, मृत्युंजय कुमार, रंगीत घोष, कपिल पाटीदार, सैय्यद जुवैर हुसेन नकबी, रोहित लाम्बा, सिद्धार्थ ईपन जॉर्ज, सुतीर्थ राय, सौमित्र चटर्जी, सिद रविनतुला, अमृत अमीरापु, एम.आर. शरण, पार्थ खरे, बोबन पॉल, गायत्री गणेश, किशन शाह, तेजस्वी वेलायुधन, अनन्या कोटिया, उत्कर्ष सक्सेना, सिद्धार्थ हरि, नवनीरज शर्मा और रोहित चन्द्रा।

यह समीक्षा माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली की टिप्पणियों और उनके द्वारा दी गई जानकारी से बहुत लाभान्वित हुई है। यह समीक्षा श्री सुरेश प्रभु, श्री नितिन गडकरी, श्री रविशंकर प्रसाद, श्री धर्मेन्द्र प्रधान, श्री पीयूष गोयल, श्री राधामोहन सिंह, श्री प्रकाश जावडेकर, श्री आर॰के॰ सिंह, श्री जयंत सिन्हा तथा माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री पी॰ राधा कृष्णन और श्री शिव प्रताप शुक्ल सहित अन्य माननीय मंत्रियों की टिप्पणियों एवं जानकारी के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करती है। यह समीक्षा श्री सुशील मोदी, श्री हसीब द्राबू, श्री टी॰एम॰ थॉमस ऐसेक, श्री मनीष सिसोदिया, श्री युद्धवीर सिंह मलिक, श्री कैलाश गहलौत, श्री युनूस खान, श्री के॰एल॰ पवार तथा श्री स्वतंत्र देव सिंह सहित माननीय राज्य सरकारों के मंत्रियों के सुझावों से भी लाभान्वित हुई है।

यह समीक्षा निम्नलिखित अधिकारियों की टिप्पणियों और उनके द्वारा दी गई जानकारी से लाभान्वित हुई है, विशेष रूप से एन॰के॰ सिंह, राजीव कुमार, अजय त्यागी, पी॰के॰ सिन्हा, नृपेन्द्र मिश्र, पी॰के॰ मिश्र, हसमुख अधिया, सुभाष, सी॰ गर्ग, अजय नारायण झा, राजीव कुमार, अरविंद मेहता, राजीव महर्षि, विरल आचार्य, विवेक देबराय, रमेश चन्द्र, प्रणब सेन, टी॰सी॰ए॰ आनंद, सुरजीत भल्ला, रितिन राय, अशीमा गोयल, रतन वातल, अमिताभ कांत, अरूणा सुंदर राजन, सुशील कुमार, वानजा एन सरना, अरूण कुमार, दुर्गा शंकर मिश्र, प्रीति सूदन, यू॰पी॰ सिंह, इंजेटी श्री निवास, सी॰के॰ मिश्र, अमरजीत सिन्हा, परमेश्वरन अय्यर, राजीव नयन चौबे, कपिल देव त्रिपाठी, शोभना के॰ पटनायक, अजय कुमार भल्ला, अरूणा शर्मा, रीता ए॰ तियोतिया, जीतेन्द्र शंकर माथुर, अश्विनी लोहानी, अजय भूषण पाण्डेय, राजीवन, के॰जे॰ रमेश, अरबिंद मोदी, गोपाल कृष्ण, टी॰आर॰ रघुनंदन, नागेश सिंह, आलोक श्रीवास्तव, विजय राघवन, राम सेवक शर्मा, विजय केलकर, वाई॰वी॰ रेड्डी, मोंटेक सिंह अहलुवालिया, आयशर जे॰ अहलूवालिया, के॰एल॰ प्रसाद, एंटनी लियानजुला, रंजिता दुबे, टी॰वी॰ सोमनाथन, प्रकाश कुमार, ए॰ गिरिधर, तरूण बजाज, सीमांचल दास, सौरभ शुक्ल, देवश्री मुखर्जी, ब्रजेन्द्र नवनीत, एस॰पी॰ सिंह परिहार, ज्योर्तिमय पोद्दार, आशुतोष शर्मा, अखिल कुमार, आशुतोष जिंदल, यू॰के॰ श्रीवास्तव, शैलेन्द्र कुमार मिश्र, के॰पी॰ कृष्णन, एम॰एस॰ साहू, नीलेन्द्र मिश्र, आनंद झा, आलोक शुक्ल, अमिताभ कुमार, गुलजार नटराजन, टी॰ राजेश्वरी, प्रशांत गोयल, एस॰ सेल्वकुमार, गोविन्द मोहन, संजीव सिन्हा, अमित मोहन गोविल, जी॰डी॰ लोहानी, संजीव पटजोशी, के॰वी॰ प्रताप, प्रवीण गर्ग, आशुतोष जिंदल, उर्वशी साधुवाणी, बी॰के॰ सिन्हा, यू॰एस॰ कुमावत, आर॰के॰ जैन, दीपांकर साहा, अनुराधा मित्रा, राजपाल, पी॰ संगीत कुमार, पी॰आर॰ मेश्राम, नंदलाल, एस॰के॰ सिन्हा, पीयूष कुमार, एस॰ के॰ तिवारी, यशवीर सिंह, अरूण कुमार, वंदना अग्रवाल, व्यासन आर॰, पी॰के॰ स्वाइन, बी॰एन॰ प्रुष्टि, वेंकटरमण आर॰ हेगड़े, रेणुका कुमार, मोहित सक्सेना, पल्ली कुण्डु, एच॰के॰ राय, रजनीश, शैलेन्द्र शर्मा, सुनील शर्मा, अश्विनी कुमार, महिमा, मनोज, आर॰एस॰ प्रशांत, वी॰ रेगी, राजेश बाधवान, पवन कुमार, वी॰ कृष्णन, गोपाल रमन आयंगर, ब्रह्म यादव, शिवानंद पई, पुलक गुहा ताकुर्ता, अरविंद श्रीवास्तव, राहुल सक्सेना, महेन्द्र पुरोहित, गार्गी और प्रीतिश कुमार त्रिपाठी, आर॰ सतीश, बैलोचन बेहरा, शोबीन्द्र अकाई, स्वाति अग्रवाल, अभिशांत पंत, विजय कुमार, सुषिमता दास गुप्ता, राजेश भाटिया, प्रमोद कुमार, डेविड रसकिन्हा, एस॰ प्रहलादन अय्यर, आशीष कुमार, आशीष गुप्ता, अश्विनी गुप्ता, सारिका, मदन, श्रीजित के॰वी॰, नेहा श्रीवास्तव, शैलेश कुमार निकिता गर्ग, अंशिका भटनागर, सुशांत सूदन, नीरज कुमार शर्मा, सलाका कुजूर, पी॰ के॰ श्रीवास्तव, वी॰एस॰ सहरावत, अरविंद पाण्डेय, जे॰ पोद्दार, गायत्री भट्टाचार्य, सुदीप्त भट्टाचार्य, विपद भंजन पाल, अरूण विष्णु कुमार, कौस्तुभ, राजीव जैन, सौम्यश्री तिवारी, मधु चांद साहू।

आर्थिक समीक्षा टीम भारत के उच्चतम न्यायालय, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों, आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी), राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनल (एन.जी.टी), राष्ट्रीय उपभोक्ता विभाग निवारण आयोग (एनसीडीआरसी), विद्युत अपीलीय अधिकरण (एपीटीईएल), राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण, (एन.सी.एल.ए.टी.), दूरसंचार विवाद निबटान तथा अपीलीय अधि करण (टीडीएसएटी), बौद्धिक सम्पदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी), सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सीईएसटीएटी), न्यायमूर्ति डी.के जैन, न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार, न्यायमूर्ति रंजनाप्रकाश देसाई, न्यायमूर्ति एस.जे. मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह, रवीन्द्र मैथानी, जी.डी. अग्रवाल, संजीव कुमार चासवाल संजय परिहार, तिरुआर शक्तिवेल, मो. फईस आलम खान, पी. वी. गणेदिवाला, सुखदा मंजुमदार, दिनेश कुमार, वैदेही, डी. काले तथा लेथराम लाडू सिंह, का आभार प्रकट करती है।

आर्थिक समीक्षा टीम अनेक शिक्षाविदों तथा प्रैक्टिशनरों का भी आभार प्रकट करती है, जिनमें ये शामिल हैं: लार्ड निकोलस स्टर्न, लार्ड अडयर टर्नर, जोय फेल्मान जस्टिन सैडंफर, दिव्यांशी वाधवा, राकेश बनर्जी, नंदन नीलकेणी, सीमा जय चन्द्रन, रिकूं मुरगई, अभिजीत बनर्जी, एस्टर डफले, फ्रेडिरगो गिल सेंडर, पूनम गुप्ता, फैबियानों सेल्वियो कोल्बानो, फैबियो सोला बिटटार, प्रताप मेहता, देवेश कपूर, देवेश राय, अशोक गुलाटी, दीपकदास गुप्ता, भानु अरुण माथुर, संदीप सुख्तांकर, हरीश दामोदरन, एंड्रियास बौर, निकोलस लार्डी, लड्जर शुग्नेच, माइकेल प्रिश्को, रानिल एम. सलगादो, निमारजित सिंह, शेखर शाह, रजत कतूरिया, अमलेन्दु घोष, रूक्मणी बनर्जी, माइकल ग्रीनस्टोन, कोर्ट जे विलमोर्ट, फरिहा कमाल, कैरोलिन फ्रयूड, रोहिणी सोमनाथन, परीक्षित घोष, हिमांशु, पुलक घोष, मौसमी दास, केजी मंसूरा, अरविंद दतर, मनीष सबरवाल, सिद्धार्थ अग्रवाल एल विश्वनाथन, सरीन वैद्य, राजीव मल्होत्रा, अपूर्वा जावडेकर, एस॰एम॰ विजयानंद, यामिनी अय्यर, चिन्मय तुम्बे, एम॰ए॰ उम्मन, मनोरंजन पटनायक, मेहुल गुप्ता, वेंकेटनारायण एस, क्षितिज बत्रा, स्वरूप मामुड़ी पुड़ी, रागिनी आहूजा, राघवी विश्वनाथ, रोहन धारिवाल, तेजस्वी मेलारकोड, वर्षा राव, गोकुल प्लाहा, देवदत्त मुखोपाध्याय, निर्मल मैथ्यू, मुइस ड्राबू, अनुष्का मित्तल, परिधि श्रीवास्तव, करन गुप्ता, माधव कुमार, अमन गुप्ता, अतिथि प्रकाश, निखिल अग्रवाल, प्रहर्ष जोहरे, श्रेय पटनायक, दक्ष और उनके सहयोगियों (सूर्य प्रकाश बी॰एस॰, अहमद पठान, हरीश नरसप्पा, श्रुति नाईक), सजिद चिनाय, आशीष गुप्ता, नीलकंठ मिश्र, कुश शाह, प्रांजल भण्डारी, यामिनी आत्मविलास, जो डाऊनी, जाक हरील्ड, निशा अग्रवाल, देव पटेल, चारल्स केन्नी, नानसी बेडसाल, चारिटी मूर, मिलन वैष्णव, अपूर्वा जाधव, रवि वर्मा, शशिधरा, राजेंद्र भाटिया, आलोक जोशी, सौम्यकांति घोष, श्रीकांत विश्वनाथन, मार्कस ब्रन्नेनमेर, अवनी कपूर, क्षितिज बत्रा, श्रीकांत विश्वनाथ, महिपाल, मिहिर भास्कर, अपर्णा कृष्णन, ब्रज पाण्डा, जी॰ के॰ किशन, मातंगी चंद्रशेखरन, अनिल नायर, चेतना योगेश वर्मा, रूपाली घनेकर, बिशाषा भट्टाचार्य, निर्मला बालकृष्णन, वी॰ राजन, पीयूष पाण्डेय, ब्रिगेडियर आर॰आर॰ सिंह (सेवानिवृत), बिल्मा वाधवा और सावित्री देवी।

उपर्युक्त के साथ-साथ, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा संगठनों ने अपने-अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनुराग अग्रवाल, आर॰पी॰ पुरी, देवाशीष हलधर, विजय कुमार, एन॰ श्रीनिवासन, आर॰ विजय कुमारी, वी॰के॰ प्रेम कुमारन, गुरमीत भारद्व ाज, प्रदीप राणा, साधना शर्मा, ज्योति बहल, सुशील शर्मा, मनीष पनवार, सुषमा, मुनाशाह, सुरेश कुमार, अनिकेत सिंह, जोध सिंह, पुनीत, ओमवीर सिंह, आर॰आर॰ मीना, सुभाष चन्द्र, राजकुमार तथा मुख्य आर्थिक सलाहकार के कार्यालय तथा आर्थिक प्रभाग के अन्य स्टाफ सदस्यों द्वारा कुशल प्रशासनिक योगदान दिया गया। प्रो॰ वी॰एस॰ बागला, रमेशबाबू अणियेरी,

सुवर्चा वसुदेव, तथा उनकी टीम ने इस समीक्षा का हिन्दी अनुवाद कार्य किया। हिंदी टंकण कार्य वाई॰एस॰ राठौर, मीना पंत, रमेशचन्द्र सुन्दरियाल, संजय प्रसाद द्वारा किया गया। समीक्षा का कवर पृष्ठ का डिजाइन जार्ज डिजाइन कोच्चि के जैकब जार्ज द्वारा किया गया, जिस कार्य में विनीत कुमार द्वारा सहयोग दिया गया। चन्द्र प्रभु आफसेट प्रिंटिंग वर्क्स प्रा॰लि॰ नौएडा ने इस समीक्षा के अंग्रेजी व हिन्दी पाठ का मुद्रण कार्य सम्पन्न किया।

अंत में हम इस समीक्षा के कार्य से जुड़े सभी व्यक्तियों के परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस दौरान धैर्य और उदारता का परिचय तो दिया ही साथ ही इस समीक्षा को तैयार करने में अपना भरपूर सहयोग एवं प्रोत्साहन भी दिया।

अरविंद सुब्रह्मण्यन
(मुख्य आर्थिक सलाहकार)
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

प्राक्कथन

पिछले वर्ष की आर्थिक समीक्षा पर हुई प्रतिक्रिया जबरदस्त, सुखद रही और जाहिर है कि इससे हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। व्यवहार-अर्थशास्त्र के अनुसार, मनुष्य नुकसान से बचने पर अधिक बल देता है, बजाय उतना ही लाभ प्राप्त करने पर। यदि यह बात सच है तो पिछले वर्ष की समीक्षा पर हुई प्रतिक्रिया ने हमें इस चिंता में डाल दिया है कि कहीं ऐसा न हो कि हम पाठकों की उम्मीदों पर खरे न उतरें।

इस वर्ष की, और मौजूदा टीम की चौथी तथा इस सरकार के कार्यकाल की अंतिम समीक्षा करते हुए एक और चुनौती यह थी कि थकान के जोखिम से बचा जाए। समीक्षा कैसे अपने दृष्टिकोण में नयापन, विश्लेषण की दृढ़ता, सामग्री की प्रासंगिकता और विचारों की ताजगी लगातार बनाकर रखे?

हमारा भाग्य अच्छा है कि हमारे बचाव के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी अनंत समृद्धि और जटिलता के साथ उपस्थित हो गई जिसने अन्वेषण के लिए हमे असीमित अवसर दिए। यह भी सौभाग्य की बात है कि पिछले चार वर्षों में आर्थिक नीति ऐसे कई नीतिगत प्रयोगों के लिए कड़ी परीक्षा रही है जिनके लिए समझ और विश्लेषण की बड़ी जरूरत है। यह भी शुक्र है कि सरकार में कार्य कर रहे हमारे सहकर्मी आंकड़े साझा करने में इतने दिलेर रहे हैं कि उनसे नए विचारों का अनुसरण किया जा सका ताकि नए तथ्य और प्रमाण सामने आ सकें।

जनता की मांग पर, हम इस वर्ष एक ही साथ खंड 1 और 2 प्रकाशित करने की परंपरा पर वापस आ गए हैं। खंड 1 में विश्लेषणात्मक सिंहावलोकन तथा और अधिक अनुसंधान एवं विश्लेषणात्मक सामग्री होती है। खंड 2 में चालू वित्त वर्ष की अधिक वर्णनात्मक समीक्षा होती है जिसमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है।

एक व्यापक विषय-वस्तु का सोच-समझकर अनुसरण किए बिना, खंड 1 का अधिकांश हमारी संभवत: अधिक दीर्घावधिक चुनौतियों पर केन्द्रित है। इसलिए, सिंहावलोकन और जीएसटी, निवेश-बचत में गिरावट, और राजकोषीय संघवाद एवं जवाबदेही जैसे सामयिक प्रासंगिकता के अध्यायों के अतिरिक्त पांच अध्याय ऐसे भी हैं जो दीर्घावधिक आर्थिक समाभिरूपता, महिला-पुरुष असमानता, जलवायु परिवर्तन और कृषि, अपीलों और न्यायिक प्रक्रिया में विलंब, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी चुनौतियों पर केन्द्रित हैं।

पिछले वर्ष की समीक्षा की तरह ही, इस बार भी अर्थव्यवस्था पर रोशनी डालने के लिए बड़े आंकड़ों की खोज की गई है और समीक्षा के लेखकों के लिए तो कुछ क्षण उनकी आंखों के सामने से पर्दा हटाने के चमत्कार के समान रहे हैं। उदाहरणार्थ, जीएसटी के कार्यान्वयन के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के विस्तृत नए आंकड़ों की उपलब्धता ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूर्णत: एक नया दृष्टिकोण दिया- भारतीय अर्थव्यवस्था का समग्र आधार पर और राज्यवार वैदेशिक और आंतरिक व्यापार, कर-जाल का आकार और वितरण, और अनौपचारिक एवं औपचारिक क्षेत्र के स्तर के संबंध में। इसी प्रकार, जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए तापमान और जलवायु के संबंध में स्थानिक रूप से उपलब्ध विविध आंकड़ों को इस्तेमाल किया गया है। जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य सर्वेक्षण (डीएचएस) तथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) से प्राप्त परिवार स्तर के आंकड़े महिलाओं से जुड़े मुद्दों के विश्लेषण का आधार रहे हैं।

इस वर्ष की समीक्षा के मुखपृष्ठ का रंग सभी महाद्वीपों में व्याप्त महिलाओं के विरूद्ध हो रही हिंसा का अंत करने के बढ़ते आंदोलन के समर्थन के प्रतीक के रूप में चुना गया है। समाज में अधिक पुत्रों की प्रबल चाह की समस्या का समाधान और महिलाओं को शिक्षा एवं प्रजनन तथा आर्थिक क्षमता से लैस करके उनका सशक्तीकरण आज भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर चुनौतियों के रूप में खड़ी है जिनका वर्णन अध्याय 7 में किया गया है।

अनेक विश्वविद्यालय समीक्षा को भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक साधन के रूप में अधिकाधिक अपना रहे हैं। इससे प्रेरित होकर, वित्त मंत्रालय के आर्थिक प्रभाग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मदद से देशभर में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए संपूर्ण मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी) शुरू किया। आशा है कि इन खंडों के बाद भी उन परंपराओं पर आगे भी कार्य किया जा सकेगा।

हमेशा की तरह, हम आर्थिक प्रभाग के कर्मचारियों के प्रति गहरा आभार व्यक्त करते हैं जिनके भागीरथ प्रयासों ने इस समीक्षा को तैयार किया। लेकिन उनका अनुसंधान केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि अनेक सरकारी कर्मचारियों ने अपना समय, सहायता और आंकड़े दिए। एक संकेतात्मक लेकिन संक्षिप्त सूची में माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन); राजस्व, जैव विज्ञान, कृषि तथा महिला और बाल-विकास विभाग; भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी); ईपीएफओ; ईएसआईसी; विभिन्न आर्थिक अपीलीय अधिकरण; केंद्रीय उत्पाद और सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीईसी); केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी); भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के सहकर्मी भी शामिल हैं।

इस समीक्षा में उत्साह और पठनीयता का मेल करने का प्रयास किया गया है। यह ऐसी चुनौती है जो उतनी ही कठिन होती जाती है, जितनी आज के युग में हम अपनी एकाग्रता को खो रहे हैं (छोटे-मोटे अखबारी और ट्विटर संदेशों के आदी होने के चलते)। इस समीक्षा का उद्देश्य हमेशा से विवरणों को मिलाकर, नए आंकड़ों के सृजन, गहन अनुसंधान और विचारोत्तेजक नीतिगत तर्कों को मिलाकर योगदानों का एक संग्रह तैयार करना रहा है।

अर्थव्यवस्था के संबंध में जीएसटी के जरिए मिले पूर्णत: एक नए परिप्रेक्ष्य के अलावा, इस समीक्षा में चर्चा किए गए कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं: क्या हम दूसरे देशों के अनुभव को समझकर अपने देश में निवेश में हो रही मौजूदा गिरावट को शीघ्र पलट सकते हैं? क्या सरकार के दूसरे और तीसरे टियर प्रत्यक्ष कर का संग्रहण कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें शक्ति प्रदान की गई है, और यदि नहीं, तो इसका क्या अर्थ है? लिंग संबंधी मुद्दों पर, क्या हमें अंतिम संतान के लिंग अनुपात पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए? किन स्थितियों में और किस हद तक और कहां, कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सबसे अधिक महसूस किया जाएगा? क्या भारत की आर्थिक दौड़ में आगे आने की चार दशक लंबी, गतिशील प्रक्रिया में कोई अवरोध होगा? क्या सरकार और न्यायपालिका को शक्तियों के सहकारी पृथक्करण पर सहमत हो जाना चाहिए, जैसाकि केन्द्र और राज्य कारोबार करने की स्थिति में सुधार लाने के लिए सहकारी संघवाद के रूप में करते हैं। क्या भारत में विश्व के शीर्ष ज्ञान सर्जकों की श्रेणी में लाने के लिए अनेक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन होने चाहिए?

ऐसे प्रयास से जुड़ी अनेक चुनौतियों के अतिरिक्त, इस समीक्षा के सभी लेखकों को पुरानेपन के खतरों से भी सावधान रहना चाहिए जैसाकि टी.एस. एलिएट ने कहा था: ''क्योंकि पिछले वर्ष के शब्द पिछले वर्ष की भाषा के थे। और अब अगले वर्ष के शब्दों को नई आवाज चाहिए''।

अरविंद सुब्रह्मण्यन
(मुख्य आर्थिक सलाहकार)
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार

संकेताक्षर

3एमएमए	3 माह चल औसत
एएवाई	अंत्योदय अन्न योजना
एराएम	अतिरिक्त संसाधन जुटाना
एएसईएएन	दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ
एएसईआर	शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक उपस्थिति
एटीएंडसी	कुल तकनीकी और वाणिज्यिक
बीसीएम	बिलियन क्यूबिक मीटर
बीई	बजट अनुमान
बीपीसीएल	भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड
बीआरआईसीएस	ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका
सीएए एंड ए	सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक
सीएडी	चालू खाता घाटा
सीएजी	भारत के महालेखा नियंत्रक
सीएजीआर	संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर
सीबीआर	कृषि जैविक संसाधन
सीएफपीआई	उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक
सीजीए	लेखा महानियंत्रक
सीजीएसटी	केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर
सीआईसी	परिचलन में मुद्रा
सीआईआरपी	कारपोरेट ऋण शोधन अक्षमता संकल्प प्रक्रिया
सीएलएसएस	ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम
सीओसी	ऋणदाताओं की समिति
सीओपी	दलों का सम्मेलन
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीआई(एएल)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कृषि श्रमिक)
सीपीआई(सी)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त)
सीपीएसई	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यम
सीपीआई(आईडब्ल्यू)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक कामगार)
सीपीआई(आरएल)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण श्रमिक)
सीआरएआर	जोखिम-भारित आस्ति अनुपात में पूंजी
सीएसए	जलवायु स्मार्ट कृषि
सीएसओ	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीटीए	सीमा शुल्क अधिनियम
सीवी	घट-बढ़ का सह-संबंध
सीडब्ल्यूपी	जनता के पास मुद्रा
डएएलवाईएस	अशक्तता समायोजित जीवत वर्ष
डीएआरआई	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीबीटीएल	एलपीजी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीडीए	दोहा विकास कार्यसूची
डीजीसीआई एंड एस	वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीआईपीएएम	निवेश एवं लोक आस्ति प्रबंधन विभाग
डीआईपीपी	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
डीआईएससीओएमएस	संवितरण कम्पनी
डीएसआईआर	विज्ञान व औद्योगिक अनुसंधान विभाग
डीटीए	घरेलू टैरिफ क्षेत्र
ईबीआरडी	यूरोपीय पुनर्निमाण और विकास बैंक
ईएफटीए	यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ
ईआईबी	यूरोपीय निवेश बैंक
ई-एनएएम	इलेक्ट्रोनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार
ईपीसीजी	पूंजी वस्तु संबंधी निर्यात संवर्धन
ईआर एंड डी	इंजिनियरिंग अनुसंधान और विकास
ईटीएफ	विनिमय व्यापारित निधि
ईयू	यूरोपीय संघ
ईडब्ल्यूआरएस	निर्वाचित महिला प्रतिनिधि
एफएओ	खाद्य और कृषि संगठन
एफसी	वित्तीय ऋणदाता
एफसीआई	भारतीय खाद्य निगम
एफडीआई	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
एफईईएस	विदेशी विनिमय अर्जन
एफएफपीआई	एफएओ खाद्य मूल्य सूचंकाक
एफआईआई	विदेशी संस्थागत निवेशक
एफआईपीबी	विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड
एफटीएएस	विदेशी पयर्टक पहुंच
एफटीपी	विदेश व्यापार नीति
एफवाई	वित्त वर्ष
जीसीए	सकल फसल क्षेत्र
जीसीसी	गल्फ सहयोग परिषद
जीसीसीए	पूंजी आस्तियों का सृजन हेतु अनुदान
जीसीएफ	सकल पूंजी निर्माण
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीएफसीई	सरकारी अंतिम उपभोग व्यय
जीएफसीएफ	सकल नियत पूंजी निर्माण
जीआईआई	वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक
जीएनआई	सकल राष्ट्रीय आय
जीएनपीए	सकल गैर-निष्पादन अग्रिम
जीपीआई	लिंग समानता सूचकांक

जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीएसटी	वस्तु और सेवाकर
जीएसवीए	सकल राज्य मूल्य वर्धन
जीटी	सकल टन
जीवीए	सकल मूल्य वर्धन
जीडब्ल्यू	गीगावाट्
एचएफसीएस	आवास वित्त कम्पनी
एचएफसीएस	हाइड्रोफ्लोरोकार्बन
एचपीसीएल	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड
एचपीआई	आवास मूल्य सूचकांक
एचवाईवीएस	अधिक उपज वाली किस्म
आईबीसी	अशोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता
आईसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
आईजीएस	अंतरराष्ट्रीय भू-स्टेशन
आईजीएसटी	एकीकृत वस्तु और सेवा कर
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईपीओ	इंडियन पेटेंट ऑफिस
आईपीपी	बौद्धिक सम्पदा उत्पाद
आईपीआर	बौद्धिक सम्पदा अधिकार
आईपीयू	अंतर-संसदीय संघ
आईआरएस	भारतीय सुदूर संवेदन
आईएसएस	ब्याज राजसहायता योजना
आईटी-बीपीएम	सूचना प्रौद्योगिकी-कारोबार प्रक्रिया प्रबंध
आईटीसी	इनपुट कर ऋण
केसीसी	किसान ऋण पत्र
केडब्ल्यूएच	किलोवाट घंटा
एलएएफ	नकदी समायोजन सुविधा
एलईबी	जन्म जीवन प्रत्याशा
एलईडी	प्रकाश-स्कंदन द्वविपथी
एलईओ	निम्न भू-कक्ष
एलएफपीआर	श्रम बल भागीदारी दर
एलआईसी	भारतीय जीवन बीमा निगम
एलपीजी	द्रवित पेट्रोलियम गैस
एलपीआई	संभारिकी निष्पादन सूचकांक
एम/ओ डीडब्ल्यूएस	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
एम/ओ एचएंडएफडब्ल्यू	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एम/ओ पीआर	पंचायती राज मंत्रालय
एम0	रिज़र्व मुद्रा
एम3	स्थूल मुद्रा
एमसी11	ग्यारहवीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस
एमडीजीएस	सहस्राब्दी विकास लक्ष्य
एमईआईएस	भारत योजना से पण्य निर्यात
एमईपी	न्यूनतम निर्यात कीमत
एमआईजी	मध्य आय समूह
एमआईपी	न्यूनतम आयात मूल्य
एमएलएएस	निर्यात सभाओं का सदस्य
एमएमआर	मातृत्व मृत्यु दर
एमएमटी	मिलियन मिट्रिक टन
एमएमटीपीए	मिलियन मिट्रिक टन प्रति वर्ष
एमएनईएस	विनिर्माण बहुराष्ट्रीय उद्यम
एमओईएफसीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमपीसी	मौद्रिक नीति समिति
एमएसएफ	सीमांत स्थायी सुविधा
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम
एमएसपी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमएसएस	बाजार स्थिरीकरण योजना
एमटी	मिट्रिक टन
एमडब्ल्यू	मेगावाट
एनएबीएआरडी	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएआरईडीसीओ	राष्ट्रीय वास्तविक सम्पदा विकास परिषद्
एनएएस	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसीएस	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनसीडीएस	अपरिवर्तनीय ऋण पत्र
एनसीएलटी	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
एनसीटी	राष्ट्रीय पूंजी क्षेत्र
एनसीडब्ल्यू	राष्ट्रीय महिला आयोग
एनडीटीएल	निवल मांग और समय देयताएं
एनएफसी	खाद्य भिन्न ऋण
एनएफएसए	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
एनएचए	राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा
एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
एनएचडीपी	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना
एनआईसीआरए	राष्ट्रीय जलवायु लचीला कृषि नवोन्मेष
एनआईटीआई	राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान
एनपीए	गैर-निष्पादन आस्तियां
एनएसडीसी	राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद्
एनएसएसओ	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय
ओडीएफ	खुले में शौच मुक्त
ओएमएसएस	खुला बाजार बिक्री योजना
ओओपीई	किया गया फुटकर खर्च
पी2पी	पीयर टू पीयर
पीए	अनंतिम वास्तविक
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली

पीई	निजी इक्विटी
पीएफसीई	निजी अंतिम उपभोग व्यय
पीएल	वैयक्तिक ऋण
पीएमएवाई	प्रधान मंत्री आवास योजना
पीएमएफबीवाई	प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना
पीएमआई	क्रय मैनेजर सूचकांक
पीएमकेएसवाई	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना
पीओएल	पेट्रोलियम तेल और स्नेहक
पीओएस	क्रय स्थान
पीपीआई	उत्पाद मूल्य सूचकांक
पीआरआईएस	पंचायती राज संस्थान
पीएसबी	सरकारी क्षेत्र बैंक
पीएसबीएस	सरकारी क्षेत्र बैंक
पीएसई	सरकारी क्षेत्र उद्यम
पीएसएफ	मूल्य स्थिरीकरण निधि
पीटीआर	छात्र-शिक्षक अनुपात
पीवीबी	निजी क्षेत्र बैंक
क्यूएफआई	अर्हक विदेशी निवेशक
आर एण्ड डी	अनुसंधान और विकास
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरइ	संशोधित अनुमान
आरइआईटीएस	वास्तविक सम्पदा निवेश न्यास
आरजीआई	भारत के महारजिस्ट्रार
आरएमएसए	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
आरओए	आस्तियों पर लाभ
आरओइ	इक्विटी पर लाभ
आरआरबीएस	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरआरआर	रिजर्व रेपो दर
आरएसए	पुनर्संरचना मानक अग्रिम
आरटीआई	शिक्षा का अधिकार
एसए	तनावग्रस्त जोखिमपूर्ण अग्रिम
एसबीएम(जी)	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एसडीजी	धारणीय विकास लक्ष्य
एसडीजीएस	धारणीय विकास लक्ष्यों
एसडीआर	विशेष आहरण अधिकार
एसइबीआई	भारत प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसइआईएस	भारत सेवा निर्यात योजना
एसजीएसटी	राज्य वस्तु और सेवा कर
एसएचजी	स्व्यं सहायता समूह
एसएलआर	सांविधिक नकदी अनुपात
एसआरआर	बीज प्रतिस्थापन दर
एसएसए	सर्व शिक्षा अभियान
एसयूयूटीआई	भारत विशिष्ट निकाय न्यास उघम
टीएएन	कर कटौती खाता संख्या
टीबी	राजकोषीय हुंडी
टीपीडीएस	लक्षित लोक वितरण प्रणाली
टीआरएआई	भारत दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
यूडीएवाई	उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना
यूडीआईएसइ	शिक्षा हेतु एकीकृत जिला सूचना प्रणाली
यूएलबीएस	शहरी स्थानीय निकाय
यूएन	संयुक्त राष्ट्र
यूएनसीटीएडी	संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएनइएससीओ	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन
यूएसडी	संयुक्त राष्ट्र डालर
यूएसजीएस	संयुक्त राष्ट्र भूगर्भीय सर्वे
यूटीएस	संघ राष्ट्र क्षेत्र
वीजीएफ	व्यवहार्यता अंतर विधियन
वीआरआर	भिन्नता प्रतिस्थापन दर
डब्ल्यूएसीआर	भारित औसत मांग दर
डब्ल्यूपीआई	खुदरा मूल्य सूचकांक
डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन

भारतीय अर्थव्यवस्था पर दस नए तथ्य

1. पंजीकृत अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करदाताओं में भारी वृद्धि हुई है।

– जीएसटी पद्धति पूर्व (चित्र 1क) की तुलना में जीएसटी के अंतर्गत विशिष्ट अप्रत्यक्ष करदाताओं में 50 प्रतिशत वृद्धि।

– इसी प्रकार से, नवम्बर, 2016 तक (चित्र 1ख) व्यक्तिगत आयकर फाइल करने वाले व्यक्तियों में लगभग 1.8 मिलियन की वृद्धि (रुझान वृद्धि से अधिक) रही है।

चित्र 1क

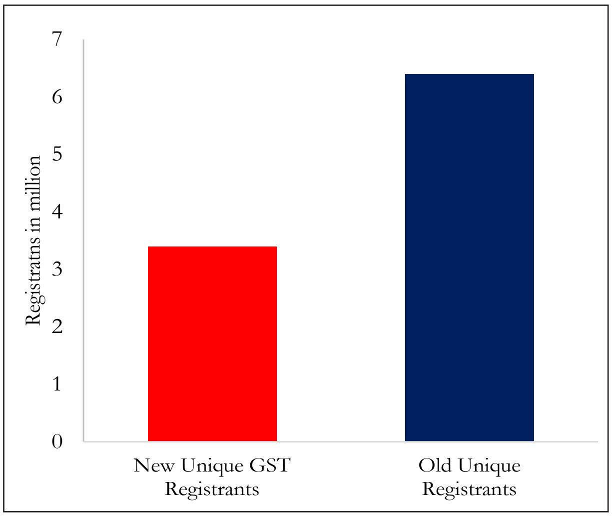

चित्र 1ख

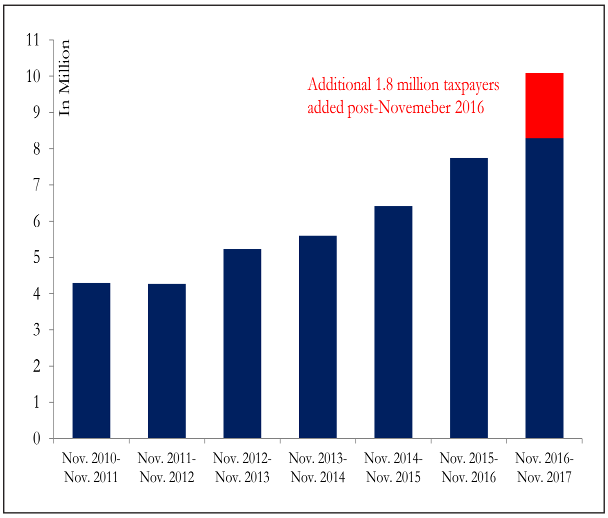

2. औपचारिक कृषितर भुगतान चिट्ठा विश्वास से कहीं ज्यादा है

– सामाजिक सुरक्षा (ईपीएफओ/ईएसआईसी) उपबंध के संदर्भ में औपचारिकता को परिभाषित किए जाने पर 30 प्रतिशत से अधिक;

– जीएसटी के दायरे में आने के संदर्भ में परिभाषित किए जाने पर 50 प्रतिशत से अधिक।

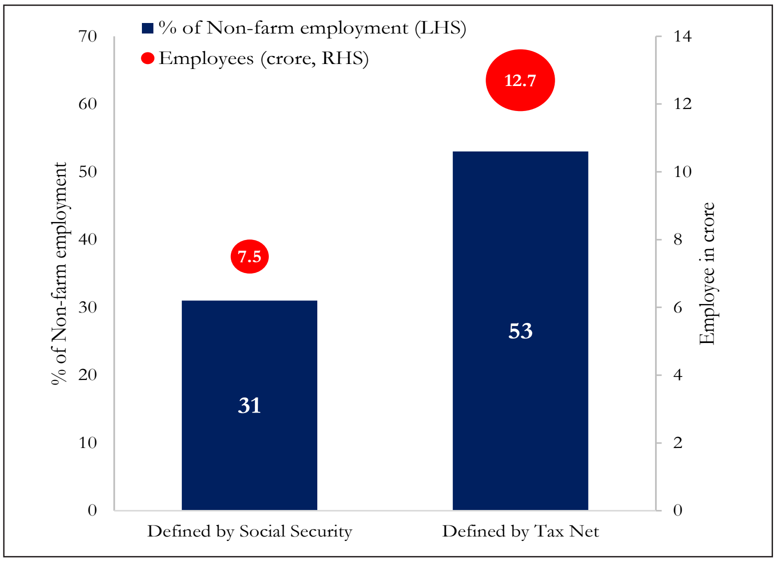

3. राज्यों की समृद्धि उनके अंतरराष्ट्रीय और अंतर-राज्यीय व्यापार से सह-संबंधित होती है।

जो राज्य अंतरराष्ट्रीय तौर पर अधिक निर्यात करते हैं और दूसरे राज्यों के साथ अधिक व्यापार करते हैं, उनके अपेक्षाकृत अधिक धनी होने की संभावना होती है। किंतु यह सह-संबंध समृद्धि और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मध्य अधिक मजबूत होता है।

अंतरराज्ट्रीय निर्यात और राज्यों की समृद्धि प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में

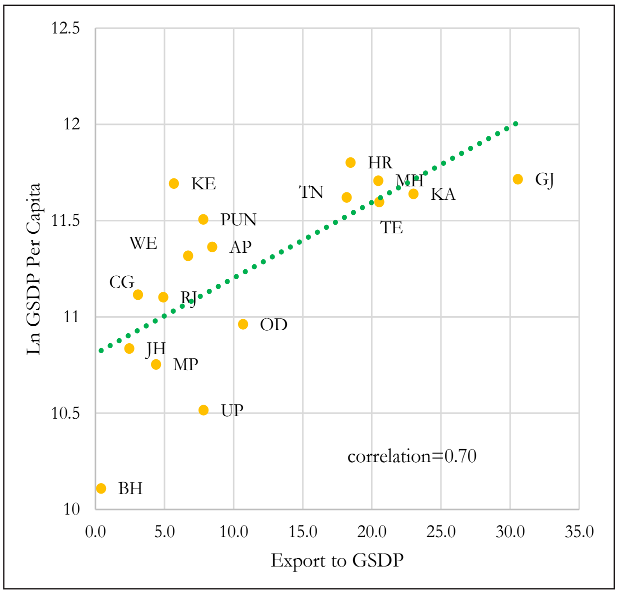

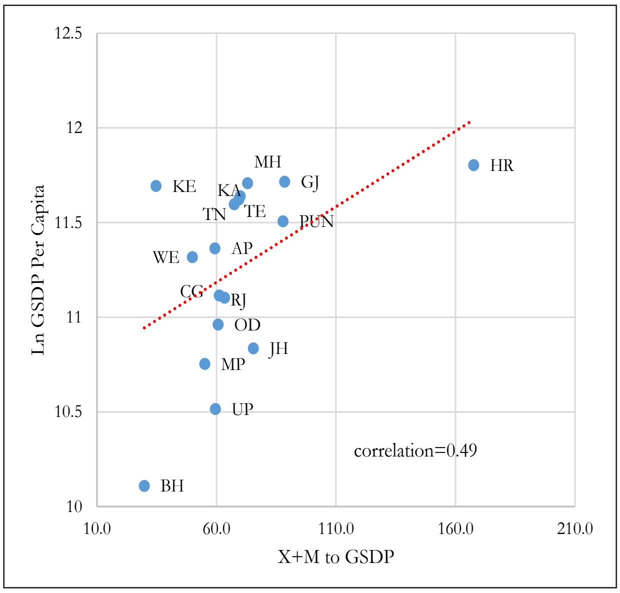

4. भारत का सुदृढ़ निर्यात ढ़ांचा अन्य बड़े देशों से काफी अधिक समतावादी है।

शीर्ष 1 प्रतिशत भारतीय फर्मों का लेखा-जोखा निर्यातों का 38 प्रतिशत है, अन्य सभी राष्ट्रों में इसका भाग काफी अधिक (ब्राजील, जर्मनी, मैक्सिको और यूएसए में क्रमशः 72, 68, 67 और 55 प्रतिशत) है। और शीर्ष 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और इसी प्रकार से अन्य के लिए यह सही है।

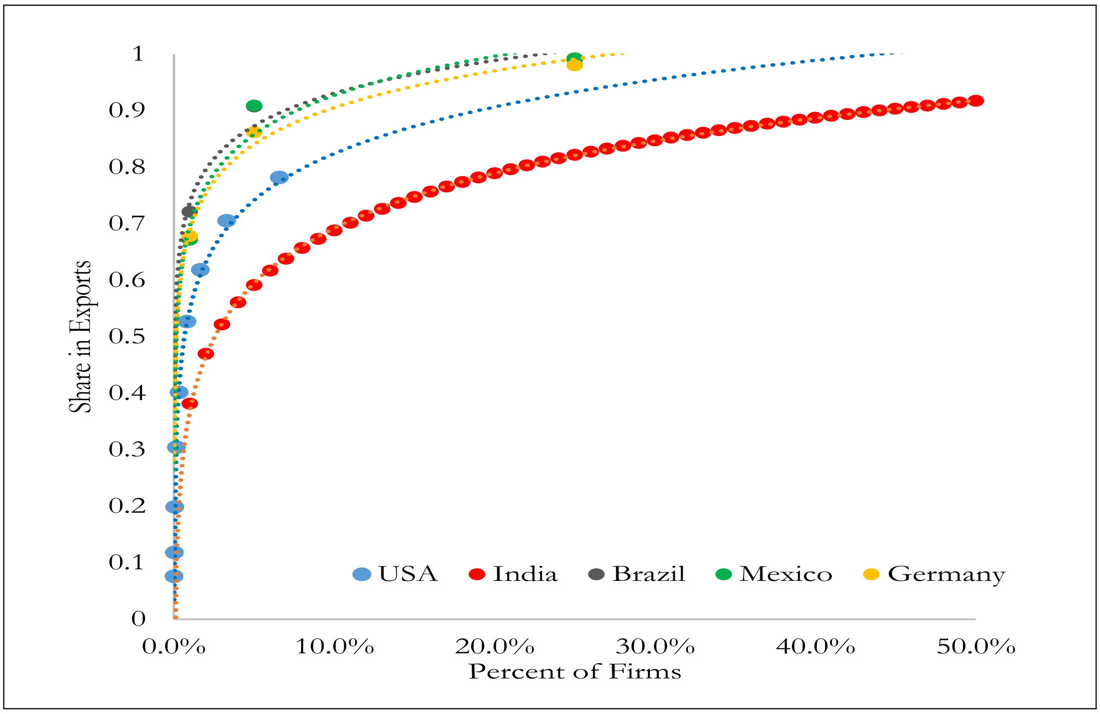

5. कपड़ा प्रोत्साहन पैकेज से रेडीमेड गारमेंटो का निर्यात संवर्धन

वर्ष 2016 में घोषित अन्तर्निहित राज्य करों (आरओएसएल) से राहत से रेडीमेड गारमेंटों (लेकिन अन्य नहीं) में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

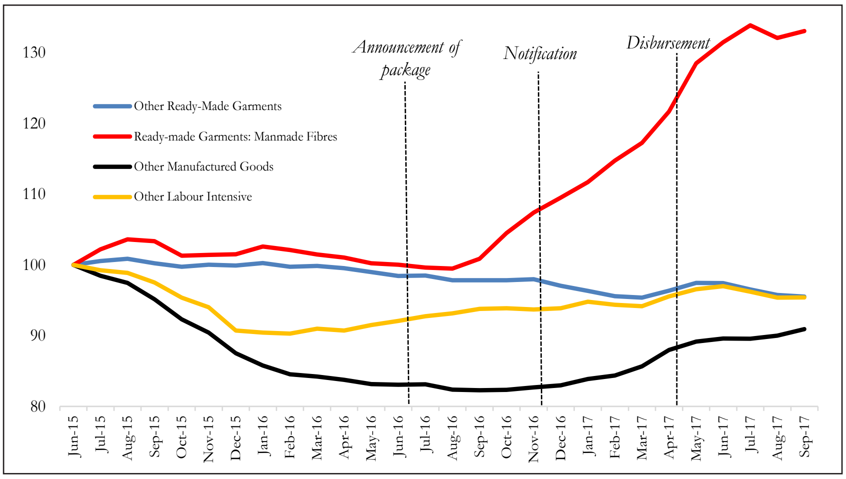

6. भारतीय समाज की पुत्र चाहत की प्रबल भावना

माता-पिता तब तक बच्चे पैदा करते रहते हैं जब तक कि उन्हें वांछित पुत्रों की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस तरह की प्रजनन क्षमता-स्टापिंग रूल से लिंगानुपात गलत दिशा में मुड़ जाता है:- यदि यह अंतिम बच्चा है तो यह पुरुषों के पक्ष में मुड़ जाता है परन्तु यदि यह अंतिम नहीं है (भारत संबंधी शीर्षस्थ दो पैनल देखें) तो यह स्त्री के पक्ष में जाएगा जहां ऐसा प्रजनन क्षमता-स्टापिंग रूल नहीं है वहां अनुपात संतुलित बना रहता है भले ही बच्चा अंतिम है अथवा नहीं (इंडोनेशिया के निचले पैनल देखें)।

जन्म पर लिंगानुपात जब बच्चा अंतिम नहीं है (2015-16) जन्म पर लिंगानुपात जब बच्चा अंतिम है।

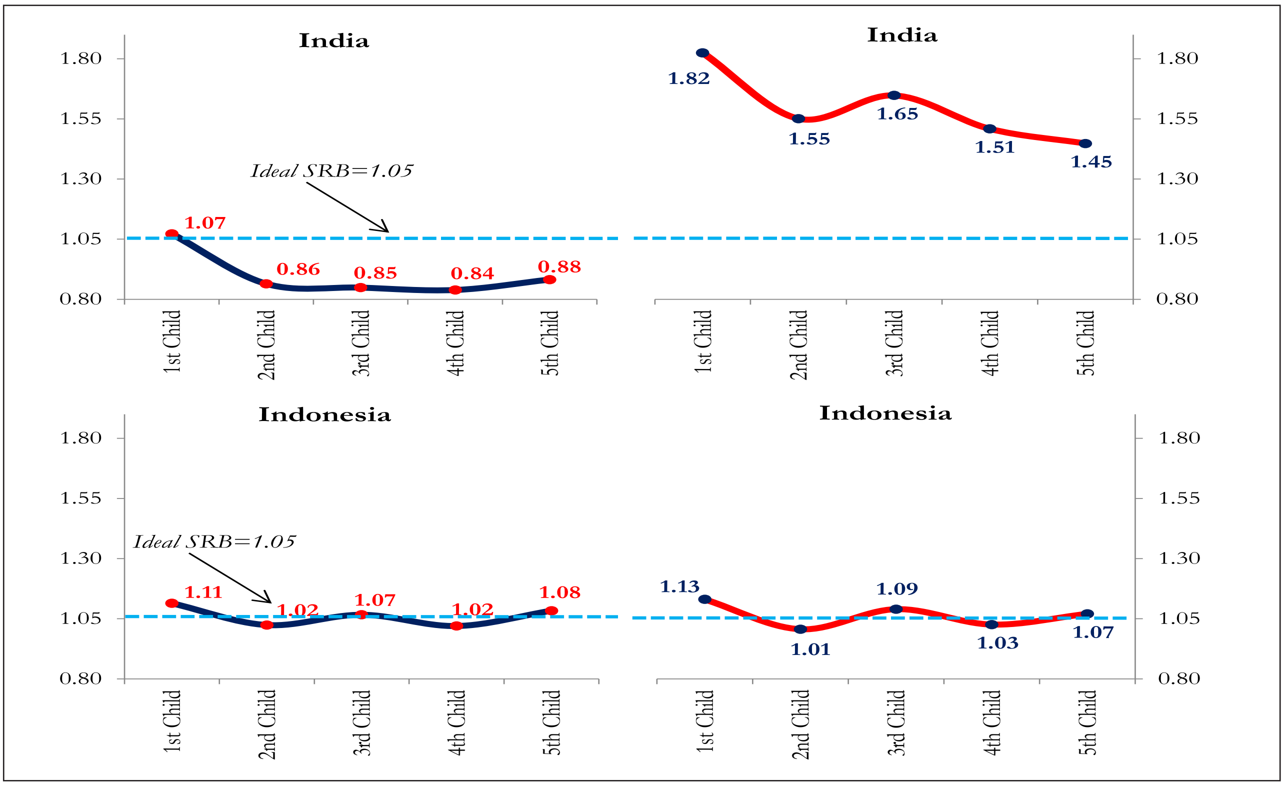

7. कर क्षेत्र में अत्यधिक मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है जिसमें सरकार कार्रवाई करके कमी ला सकती है।

कर विभाग में पिटिशन की दर बहुत ऊंची है इसके बावजूद मुकदमेबाजी में जीत की दर बहुत कम और भी कम होती जा रही है (30 प्रतिशत से भी कम)।

- हित मूल्य के 56 प्रतिशत मामलों में से केवल 2 प्रतिशत;
- हित मूल्य का 1.8 प्रतिशत के लिए लगभग 66 प्रतिशत मामले लंबित (प्रत्येक 10 लाख रुपए से कम)।

कर विभाग संबंधी पीटिशन दर और सफलता दर मार्च 2017

	Direct Tax Cases		Indirect Tax Cases	
Court	Success Rate	Petition Rate	Success Rate	Petition Rate
Supreme Court	27%	87%	11%	63%
High Courts	13%	83%	46%	39%
ITAT/CESTAT	27%*	88%*	12%	20%

*अनंतिम अनुमान

8. बचत को बढ़ावा देने से अधिक महत्वपूर्ण निवेश में नई जान फूंकना और बढ़ावा देना अधिक महत्वपूर्ण है

पूरे देश के अनुभवों से यह बात पता चलती है कि निवेश के कम होने के बाद विकास की गति धीमी हुई है परन्तु यह जरूरी नहीं है कि इस धीमी गति का कारण बचत है।

निवेश में परिवर्तन और विकास में परिवर्तन

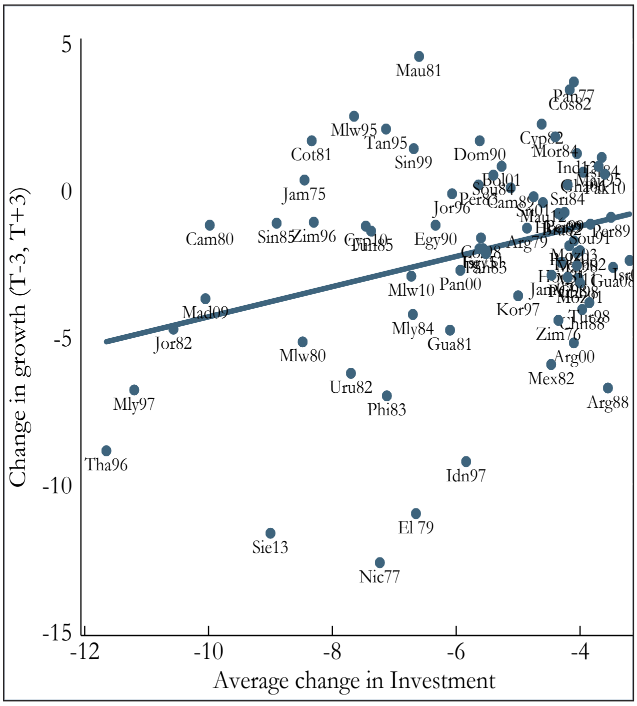

बचत में परिवर्तन और विकास में परिवर्तन

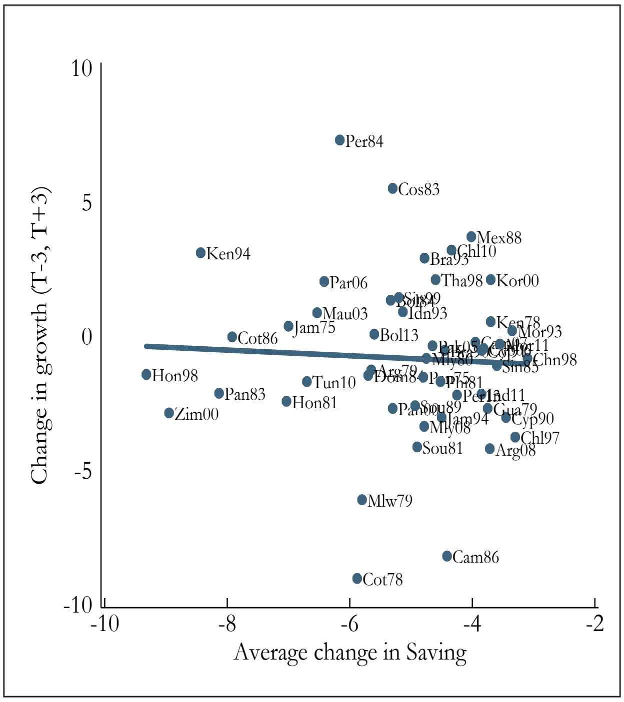

9. भारतीय राज्यों और स्थानीय सरकारों द्वारा निजी प्रत्यक्ष कर संग्रह अन्य संघीय देशों में उनके समकक्ष करों के संग्रह से काफी कम है।

यह हिस्सा उनकी वास्तविक प्रत्यक्ष कराधान शक्तियों की अपेक्षा कम है।

कुल राजस्व में प्रत्यक्ष करः राज्य और स्थानीय सरकार (प्रतिशत में)

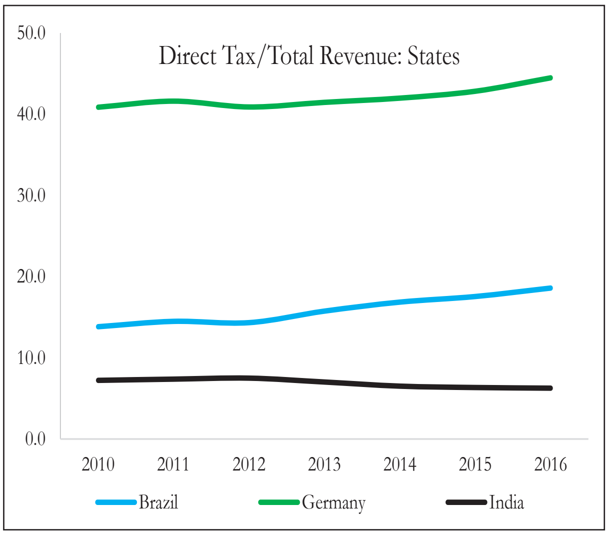

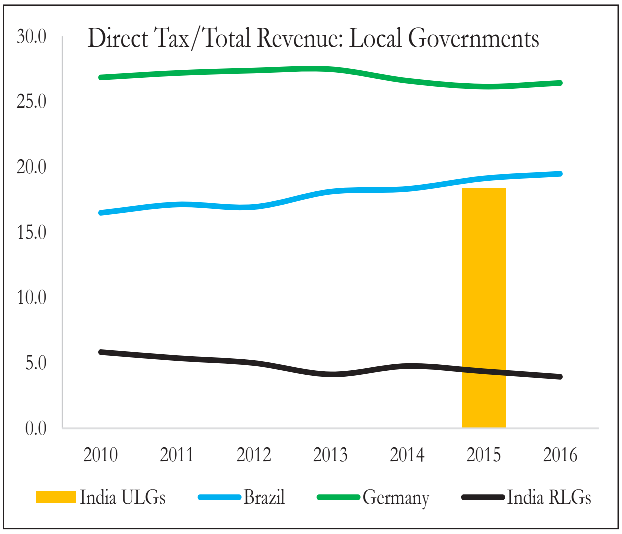

10. जलवायु परिवर्तन का फुटप्रिन्ट स्पष्ट है और चरम मौसम से कृषि उपजों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- मौसम के प्रभाव का अनुभव केवल अत्यधिक तापमान वृद्धि और वर्षा की कमी से ही किया जाता है।
- यह प्रभाव सिंचित क्षेत्रों की अपेक्षा गैर-सिंचित क्षेत्रों में दुगना अधिक होता है।

तापमान परिवर्तनों **का अंतरिक्षी/वितरण (वर्ष 2005-2015 के औसत और 1950-1980 के औसत के मध्य डिग्री सेल्सियस परिवर्तन)**

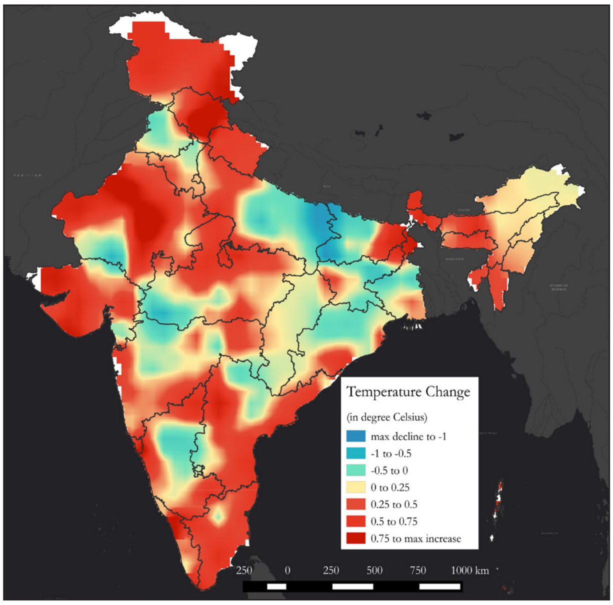

तापमान डिसाइल के अनुसार तापमान परिवर्तनों का कृषि उपज पर प्रभाव (खरीफ प्रतिशत)